केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 72 शनिवार 3 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

चैंपियनशिप 2026 के प्रतिभागी पुरस्कृत

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सुपरकिड्ज एकेडमी द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय चैपियनशिप 2026 के प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए स्टेशन रोड स्थित होटल में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एलकेजी से 8वीं तक के प्रतिभागियों को ओवरऑल चौंपियन, चौंपियन, गोल्ड, सिल्वर एवं मेरिट वर्ग में ट्रॉफी मेडल नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ल और विशिष्ट अतिथि अंकुर वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि तथा अतिथि गण एक्यूप्रेशर चिकित्सक डॉक्टर नवीन सिंह, व्यवसायी वेद मेहंदीरत्ता, उत्तर प्रदेश कसौधन महासभा के अध्यक्ष पवन कसौधन, राज्य पिछड़ा आयोग के रमा शंकर साहू, महिला कसौधन समाज की अध्यक्ष श्रीमती कंचन गुप्ता, कसौधान समाज के अध्यक्ष राजेंद्र कसौधन, कसौधन महा सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष बृज किशोर कसौधन आदि ने बच्चों को पुरस्कृत किया।

ओवरऑल चैंपियन कैटेगरी में आरुष अग्रवाल कक्षा 4, शिवम् पाण्डेय यूकेजी तथा इरा अनुपम श्रीवास्तव कक्षा 2 को चौंपियन ट्रॉफी एवं 2100 नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सुपरकिड्ज के नन्हे विद्यार्थियों ने मंच पर मात्र कुछ सेकेंडों में बिना किसी बाहरी उपकरण या पेन पेपर के कठिन गणितीय प्रश्नों का उत्तर देकर सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अचंभित कर दिया। जोड़ घटाना गुणा भाग, 1000 तक का पहाड़ा, मल्टी टास्किंग जैसी क्षमताओं का प्रदर्शन जब नन्ही प्रतिभाओं ने प्रस्तुत किया तो लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे।

संस्थापक सौरभ तुलस्यान ने प्रतियोगिता एवं सुपरकिड्ज द्वारा संचालित कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बस्ती जनपद में नौनिहालों की प्रतिभाओं को एक मंच पर सम्मानित करने के लिए जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष सुपरकिड्स द्वारा किया जाता है, जिसमें मेंटल मैथ, जनरल अवेयरनेस, स्पीड हैंडराइटिंग के प्रश्न पत्र होते हैं, जो बच्चों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव प्रदान करते हैं।

युवक ने काट लिया गला, मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । छावनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने ब्लेड से अपना गला काट लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे सीएचसी विक्रमजोत लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार दोपहर की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नटुवा ग्राम पंचायत के पूरे सुखरामपुरवा निवासी राहुल (22) पुत्र आशाराम के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, राहुल घर से कुछ दूर बैठा था। इसी दौरान उसने सेविंग ब्लेड से अपना गला काट लिया। ज्यादा खून बहने पर परिजन उसे आनन–फानन में सीएचसी विक्रमजोत ले गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

राहुल के भाई सुरेंद्र ने बताया कि गुरुवार को राहुल बाहर जाकर कमाने की बात कह रहा था। इसके बाद वह रातभर घर नहीं आया। शुक्रवार को घर से कुछ दूरी पर उसके मिलने और फिर गला काटने की घटना हुई। ग्रामीणों के मुताबिक, राहुल मानसिक रूप से परेशान रहता था। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था।

छावनी थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ज्ञानेश कुमार के बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन

मुम्बई (आभा)। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के विरोध में भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने 'अभिजीत दिपके वापस जाओ' के नारे लगाए। हालांकि, नारे लगाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने किस वजह से दिपके का विरोध किया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस प्रदर्शन में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी शामिल हुईं। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और गायक विशाल ददलानी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

मुंबई के मध्य में स्थित शिवाजी पार्क में शुक्रवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे।

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा हाथों में नारे लिखी तख्तियां और तिरंगा लेकर मैदान में पहुंचे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह समेत कई लोग भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे।

गोपेश्वर त्रिपाठी को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाये जाने पर प्रसन्नता

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरक्ष प्रान्त के अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी को मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाये जाने पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता का माहौल है। पार्टी के अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर त्रिपाठी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसी कड़ी में शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान की कड़ी में गोपेश्वर त्रिपाठी के संयोजन में गांधी जयंती के अवसर पर मालीटोला काली मंदिर के निकट वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है, पूरा प्रयास होगा कि उस पर खरा उतरूं। कहा कि भाजपा किसान मोर्चा किसान हितों के लिये निरन्तर संघर्षरत है। भाजपा की सरकार में किसानों को सर्वाधिक अवसर मिले हैं और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के साथ ही वैज्ञानिक ढंग से खेती के प्रशिक्षण के साथ संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कहा कि भाजपा किसान मोर्चा किसान हितों के लिये समर्पित है। सेवा संकल्प अभियान की कड़ी में वृहद स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से गोरक्ष प्रान्त के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामानन्द नन्हें, सभासद दिनेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, राजन ठाकुर, आलोक पाण्डेय, सुधाकर पाण्डेय, सचिन शुक्ल, शेष नारायन गुप्ता, ताड़क जायसवाल, मनमोहन श्रीवास्तव 'काजू', राजकुमार शुक्ल के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

विश्व कायस्थ महासंघ के पदाधिकारी सपा में शामिल

मासिक बैठक में बूथ स्तर के मजबूती पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष और विधायक महेन्द्रनाथ यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बूथ स्तर पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुये समीक्षा के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयन्ती पर याद किया गया। कार्यक्रम में विश्व कायस्थ महासंघ के संस्थापक कमलेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पदाधिकारियों और सदस्यों ने सपा की सदस्यता ग्रहण किया ।

सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि बापू– शास्त्री विचार के रूप में पूरी दुनियां में प्रतिष्ठित है। दोनों महापुरूषों को युगों तक याद किया जायेगा। उन्होने सपा नेताओं, पदाधिकारियों का आवाहन किया कि वे जनता के बीच बने रहे, उन तक समाजवादी विचार धारा और पार्टी के नीति, कार्यक्रम लेकर जाय और यथा संभव जरूरतमंदों की मदद के साथ ही उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार के

–समाजवादियों ने किया बापू-शास्त्री को नमन्: योगदान पर विमर्श

योजनाओं से लाभान्वित कराने की दिशा में सहयोग करें। कहा कि एक तरह से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा के कुनीतियों से त्रस्त जनता बदलाव का मन बना चुकी है। प्रदेश में सपा की मजबूत सरकार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिये पूरी तैयारियों में जुट जाय।

विधायक कविन्द्र चौधरी अतुल, पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, वरिष्ठ नेता दयाशंकर मिश्र, जावेद पिण्डारी, मो. स्वालेह, समीर चौधरी, पूर्व अध्यक्ष राजकपूर यादव, आर.डी. निषाद, जय श्री लाल, हरीश गौतम, सीताराम चौहान, प्रवीण पाठक, निजामुद्दीन, राघवेन्द्र सिंह, मो. सलीम, गीता भारती, इन्द्रावती शुक्ल, विजय विक्रम आर्य, डा. देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव आदि ने बापू– शास्त्री को नमन् करते हुये कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से पार्टी के नीति, कार्यक्रमों से लोगों को जोड़े।

समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में विश्व कायस्थ महासंघ के संस्थापक कमलेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मनीष कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार सिन्हा, रनधीर सिंह कायस्थ, हरश्याम श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, शुभम कश्यप, अतुल श्रीवास्तव, दीपू श्रीवास्तव, अंकित दीप श्रीवास्तव, मोनू, पुरूषोत्तम राना, सोनू कुमार, मनीष जायसवाल, विशाल श्रीवास्तव, कन्हैया कुमार, राजेश श्रीवास्तव आदि को सपा जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव ने सपा में शामिल करते हुये सदस्य बनाया। बापू– शास्त्री जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा. राम प्रकाश सुमन, गुलाब चन्द सोनकर, राम सिंह यादव, प्रिया श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी, प्रेमा निषाद, रन बहादुर यादव, प्रशान्त यादव, मो. युनूस, तूफानी यादव, गौरीशंकर, विलाल अहमद, अजीत सिंह, बब्लू तिवारी, वैजनाथ शर्मा, अखिलेश यादव, नितराम चौधरी, सदावृक्ष तिवारी, निसार अहमद, चन्द्रभूषण यादव, श्याम सुन्दर, धर्मराज, मधुबन यादव, जर्सी यादव, राम सुरेश सोनकर, सुशील यादव, परशुराम यादव, प्रमोद यादव, चन्द्रिका के साथ ही पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बापू– शास्त्री जयंती पर विविध आयोजन

महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आवाहन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रपिता महॉत्मा गॉधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे जिले में समारोहपूर्वक मनाई गई। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की शपथ दिलायी गयी। दोनों महापुरुषों के चित्र का अनावरण करके फूल माला चढ़ाई गई।

मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव ने राष्ट्रध्वज फहराया, सभी ने तिरंगे का अभिवादन किया व राष्ट्रगान गाया गया। सभागार में उन्होने महात्मा गॉधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया और कहा कि दोनों महापुरूषों का व्यक्तित्व व कृतित्व सादगीपूर्ण रहा। हम सभी को इनके आदर्शो को अपने जीवन में लागू करना चाहिए।

गोष्ठी में अपर आयुक्त प्रशासन मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि दोनों महापुरूषों ने देश की जटिल परिस्थितियों का अध्ययन कर देश को आजादी दिलाया। उन्होने अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए अपने नारे व विचारों से प्रभावी योगदान दिया। आज के पुनीत अवसर पर हमें महापुरूषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके जीवन में सत्य, अहिंसा का प्रयोग हमारे लिए प्रेरणादायी है। हम अपनी कथनी व करनी में कोई अन्तर ना रखें।

अपर आयुक्त न्यायिक सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि महात्मा गॉधी व शास्त्री जी सादगीपूर्ण जीवन

जिया। इससे प्रेरित हो करके उनके साथ सम्पूर्ण जनमानस आजादी के आन्दोलन में जाग्रित होकर अपना योगदान दिया। संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने कहा कि सत्य और अहिंसा गॉधी जी के दो अचूक अस्त्र थे, जिससे भारत वर्ष को बहुत बड़ी सफलता मिली। हम अपने उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी का पूरी सत्यनिष्ठा से निर्वहन करें। महापुरूषो के प्रति यही सच्ची श्रद्धाजंलि होगी।

इस अवसर पर सरस्वती बालिका विद्यालय रामबाग की संगीत शिक्षिका पंखुडी मिश्रा के निर्देशन में अर्पिता, अदिति, रक्षिता छात्राओं द्वारा गॉधी जी का प्रिय भजन प्रस्तुत किया गया। सुन्दर प्रस्तुति के लिए सभी को पुरस्कृत किया गया। उपश्रमायुक्त रचना केशरवानी, निरीक्षक राजकीय कार्यालय अश्वनी कन्नौजिया, प्रशासनिक अधिकारी संतोष पाण्डेय, बजंरग बली पाण्डेय, शैलेष श्रीवास्तव, अनुपम, संदीप, सौरभ, रमेश कुमार, ओ.पी. चौधरी, अमित, सहित कार्यालय के स्टाफ उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने किया।

कलेक्ट्रेट में महात्मा गॉधी के 157वॉ जन्म दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने ध्वजारोहण किया। सामूहिक राष्ट्रगान के बाद एकता और अखण्डता की शपथ दिलायी गयी। उन्होने गॉधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सभाकक्ष में आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए उन्होने सत्य, अहिंसा व सेवा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के परिपेक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी व लाल बहादुर के सिद्धातो पर चलने का आह्ववान किया। उन्होने कहा कि आम जनमानस आपके कार्यालय में समस्या लेकर आये तो उसकी समस्या को शीघ्र निस्तारित किया जाय। उन्होने कहा कि उच्च पद पर रह कर भी व्यक्ति को जीवन में सादगी का पालन करना चाहिए। उन्होने कहा कि महापुरूषो द्वारा जो बाते बतायी गयी है, उनका चिन्तन करना चाहिए। 02 अक्टूॅबर के दिन उनके जीवन पर आधारित किताबों को पढना चाहिए, उनके आचार–विचार को अपने जीवन में ढालना चाहिए।

उन्होने कहा कि आज विविधता में एकता स्थापित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए तथा उनके संदेश को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए, जिससे की गॉधी जी का सपना साकार हो सके। उन्होने यह भी कहा कि गॉधी जी का पूरा जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा की मिसाल है। उन्होने अपने विचार और आन्दोलनों से न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया बल्कि पूरे विश्व को शान्ति और मानवता का मार्ग दिखाया। आज के परिवेश में गॉधी जी के विचार और भी प्रासंगिग है। उन्होने कहा कि समाज में स्वच्छता, समानता और सौहार्द स्थापित करना ही गॉधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने गॉधी कला भवन में पहुॅचकर महात्मा गॉधी के प्रतिमा पर माल्यापर्ण तथा परिसर में आम का पौधरोपड़ किया।

इस अवसर पर जीआईसी की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया व जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत व उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती सहित अन्य अधिकारियों ने भी उनके सत्य के आग्रह की विशेषता बताया।

कार्यक्रम का संचालन मो. काजी अनवार हुसैन ने किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी उमाकान्त तिवारी, हिमांशु कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी वीना सिंह, धनन्जय कुमार सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, रामदत्त मिश्रा, अशोक कन्नौजिया, पिंकी श्रीवास्तव, सॉजमा खातून, रंजीत रंजन, नाजिर प्रेम प्रकाश, शिक्षिका मानवी सिंह सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।

विश्व हिन्दू महासंघ की बैठक में संगठन विस्तार और आगामी त्योहारों को लेकर मंथन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विश्व हिन्दू महासंघ जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक शुक्रवार को आदित्य अवंतिका मैरिज हाल, फुटाहिया के निकट संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष, अधिवक्ता प्रकोष्ठ कुलदीप मिश्रा उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज को जागरूक करते हुए सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि कुलदीप मिश्रा ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर आगामी हिन्दू त्योहारों को लेकर सजग और सक्रिय रहना चाहिए, ताकि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत व गतिशील बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों के निर्वहन पर जोर दिया।

बैठक के दौरान संगठन में

–हिन्दू समाज की एकजुटता आवश्यक– अखिलेश सिंह

नवनियुक्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों में बालकृष्ण सिंह एवं राजकुमार उर्फ मंटू चौधरी को रामनगर, रुधौली, गौर और सल्टौआ क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री, संदीप कमलापुरी को परशुरामपुर, हरैया और विक्रमजोत ब्लॉक क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री तथा सौरभ चतुर्वेदी को कप्तानगंज, दुबौलिया और बहादुरपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष और विपिन सिंह को बस्ती सदर, बनकटी और साऊंघाट का क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नेतृत्व, ऊर्जा और सक्रियता के माध्यम से संगठन को गांव–गांव तक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में अमरजीत सिंह, सौरभ त्रिपाठी, विवेक श्रीवास्तव, पूनम सिंह, डॉ. पंकज त्रिपाठी, बाबा जयप्रकाश दास, शिवलाल प्रेमी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, राकेश सिंह, विपिन सिंह, सौरभ चतुर्वेदी, राजकुमार उर्फ मंटू चौधरी, बालकृष्ण सिंह बबलू, संदीप कमलापुरी, अरुण सिंह, परमानंद गुप्ता, अमित त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, विकास प्रजापति, सुनील मिश्रा, जमुना प्रसाद, चंद्रमा त्रिपाठी सानू, ज्योति भूषण उर्फ सोनार सिंह, उज्जवल सिंह, आलोक सिंह, शैलेश शुक्ला, अभिषेक अग्रहरी, रंजीत यादव, विकास वर्मा, महेंद्र पाठक, शुभम शुक्ला, रूपनारायण गौड़, गिरजेश पाल, विष्णु प्रसाद, सुमित, राज कपूर, अभिषेक उपाध्याय, प्रेम शंकर शुक्ला, अनुसूया पांडे और डॉ. रेखा मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भानपुर की जन चौपाल में गूंजे जनसमस्याओं के मुद्देः अरविन्द राजभर ने कार्यकर्ताओं को दिया संगठन मजबूत करने का संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत भानपुर में भाजपा नेता मनोज सिंह के संयोजन में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अरविन्द राजभर ने क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। जन चौपाल में स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अरविन्द राजभर ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि जन चौपाल का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया।

कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सुभासपा नेता अरविन्द राजभर ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 को देखते हुए संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता महत्वपूर्ण है। जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा। जन–जन की सेवा और

उनके अधिकार एवं सम्मान के लिए निरंतर काम करना सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प होना चाहिए।

जन चौपाल में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बनाए रखने तथा क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श हुआ। कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र की परिस्थितियों और जनता से जुड़े विषयों को लेकर अपने सुझाव रखे।

इसके पूर्व सुभासपा नेता अरविन्द राजभर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। आयोजक मनोज सिंह ने मुख्य अतिथि अरविंद राजभर का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं का साथ एवं सहयोग मिलता रहा तो नगर पंचायत भानपुर को विकास के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भाजपा संगीता प्रताप जायसवाल, जिलाध्यक्ष सुभासपा मनोज राजभर, सुरेन्द्र सिंह,लल्लन सिंह, विकास शर्मा,शनकी श्रीवास्तव, विक्की शर्मा, बृजेश सिंह सोनू सिंह, राकेश सिंह,मंटू दूबे,मोनू पाठक,सूनील पाण्डेय, अनिल मिश्रा, भोला सिंह, विक्की सिंह, अनिल सिंह, शिवराम सिंह,दीपक गौतम,आकाश सिंह,अभय सिंह,भोलू सिंह, मुकेश यादव,अजय चौधरी, अन्य गणमान्य नागरिक जन मौजूद रहें।

रंग लायी जर्जर सड़कों के मुद्दे पर सुभासपा नेता प्रमोद चौधरी की पहलः प्रशासन ने कार्रवाई के लिए दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सल्टौआ गोपालपुर विकासखण्ड क्षेत्र में जर्जर संपर्क मार्गों के निर्माण और पुनर्निर्माण की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी की ओर से उठाई गई आवाज का असर अब प्रशासनिक स्तर पर दिखाई देने लगा है। ग्राम गोविंदापुर से ग्राम जाता कर्मा तथा बस्ती–डुमरियागंज मुख्य मार्ग से महुआ डाबर को जोड़ने वाले जर्जर संपर्क मार्गों के निर्माण को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर उपजिलाधिकारी भानपुर कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रमोद कुमार चौधरी ने 22 सितंबर 2026 को उपजिलाधिकारी भानपुर को ज्ञापन सौंपकर दोनों जर्जर मार्गों के शीघ्र निर्माणध्पुनर्निर्माण की मांग की थी। ज्ञापन में बताया गया था कि मार्ग लंबे समय से खराब हैं और जगह–जगह गहरे गड्ढों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में शुरू कराने की मांग की गई थी।

मामले में उपजिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में

ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उल्लेख किया गया है कि ज्ञापन में 30 दिवस के भीतर सड़क निर्माण/ पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने की मांग की गई है। प्रशासन की ओर से संबंधित स्तर पर प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर कराने तथा की गई कार्रवाई से प्रमोद कुमार चौधरी को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक पत्र में संबंधित अधिकारियों को प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इससे सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहे प्रयासों को प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

सुभासपा नेता प्रमोद कुमार चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से जर्जर सड़कों की समस्या झेल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के बाद प्रशासन द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश देना सकारात्मक कदम है। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रस्तावित कार्य योजना में इन सड़कों को शामिल कर धरातल पर निर्माण कार्य कब शुरू कराया जाता है।

चौधरी ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र की जनता की बुनियादी समस्याओं को प्रशासन के सामने मजबूती से रखना है और सड़क निर्माण होने तक इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 3 अक्टूबर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी के प्रश्न

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर चुनावी व्यवस्था, चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाताओं के भरोसे से जुड़े सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। देश में होने वाले चुनावों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी आयोग के पास होती है। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों को लेकर उठने वाले सवालों का असर केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम मतदाता भी उससे प्रभावित होता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और चुनाव आयोग को लेकर उठने वाले सवालों को सामान्य राजनीतिक बहस मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के फैसलों से करोड़ों मतदाताओं के अधिकार जुड़े होते हैं। इसलिए जब चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव या आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर किसी राजनीतिक दल, संगठन या नागरिक समूह की ओर से आपत्ति सामने आती है, तो उसका स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी हो जाता है।

ज्ञानेश कुमार को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में संशोधन और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि चुनाव से जुड़ी हर प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाया जाए, ताकि किसी मतदाता के मन में अपने मताधिकार को लेकर किसी तरह की आशंका न रहे। दूसरी ओर चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को समय–समय पर अपडेट करना जरूरी है, ताकि गलत, दोहरे या ऐसे नामों को हटाया जा सके जो अब संबंधित क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं।

मतदाता सूची में सुधार अपने आप में चुनावी व्यवस्था का जरूरी हिस्सा है। देश में बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई बार एक ही व्यक्ति का नाम अलग–अलग जगहों पर दर्ज हो सकता है। इसलिए मतदाता सूची को समय–समय पर सही करना आवश्यक है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से न हटे और हर बदलाव की जानकारी स्पष्ट तरीके से उपलब्ध हो।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में चुनाव कराना बहुत जटिल काम है। करोड़ों मतदाता, लाखों मतदान केंद्र और बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनावी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटी सी गलती भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट और भरोसेमंद बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

लोकतंत्र में असहमति के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। राजनीतिक दल, नागरिक संगठन और आम लोग किसी भी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सकते हैं। सवाल पूछना लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सवालों के साथ तथ्य और प्रमाण भी जरूरी हैं। किसी संस्था की आलोचना यदि ठोस तथ्यों के आधार पर होगी तो उससे व्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ेगी। वहीं केवल आरोप–प्रत्यारोप तक सीमित बहस से समस्या का समाधान निकलना मुश्किल होता है।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास है। आयोग के पास कानून और संविधान से मिले अधिकार हैं, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की वास्तविक ताकत उसके प्रति लोगों के भरोसे से आती है। यदि मतदाता को यह विश्वास हो कि उसकी जानकारी सुरक्षित है, उसका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है और उसका वोट निष्पक्ष तरीके से दर्ज होगा, तभी चुनावी व्यवस्था मजबूत मानी जाएगी।

इसी कारण चुनाव आयोग को भी बदलती परिस्थितियों के साथ संवाद की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। आज के समय में चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेकर कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे में यदि किसी प्रक्रिया को लेकर भ्रम पैदा होता है तो आयोग की ओर से समय पर स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है। जितनी जल्दी और सरल भाषा में जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही गलतफहमी और संदेह की गुंजाइश कम होगी।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चुनावी व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जनता के सामने किसी भी मुद्दे को रखते समय तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएं तो यह भी बताया जाना चाहिए कि समस्या कहां है, किस प्रक्रिया में आपत्ति है और उसके समाधान के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को केवल राजनीतिक बयान के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसके तथ्यों की जांच करना जरूरी है। मतदाता सूची में बदलाव, चुनावी नियम या आयोग के किसी फैसले को लेकर चर्चा हो तो लोगों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इससे जनता किसी भी मुद्दे को अपनी समझ के आधार पर देख सकेगी।

आज चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के विश्वास को लगातार मजबूत बनाए रखना भी है। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल, मतदाता सूची के लगातार संशोधन और चुनावी प्रक्रिया में आने वाले नए बदलावों के बीच लोगों को यह समझाना जरूरी है कि व्यवस्था किस तरह काम करती है।

किसी भी संवैधानिक संस्था की आलोचना और उसका सम्मान एक–दूसरे के विरोधी नहीं हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं से सवाल पूछे जा सकते हैं और संस्थाओं को उन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। इससे संस्था कमजोर नहीं होती, बल्कि उसकी जवाबदेही मजबूत होती है। इसी तरह राजनीतिक विरोध का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रही बहस को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह बहस केवल किसी एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में चुनावी व्यवस्था, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और आम मतदाता का भरोसा है। इन सवालों का समाधान आरोप और प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि स्पष्ट जानकारी, प्रमाण और संवाद से ही निकलेगा।

भारत में चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं। यह वह माध्यम है जिसके जरिए आम नागरिक अपनी राजनीतिक भागीदारी दर्ज कराता है। जब कोई मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचता है तो वह इस भरोसे के साथ अपना वोट देता है कि उसकी आवाज निष्पक्ष तरीके से दर्ज होगी। इसलिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े किसी भी विवाद को गंभीरता से लेना जरूरी है। अच्छा हो कि ज्ञानेश कुमार प्रकरण का रचनात्मक पटाक्षेप हो और मतदाताओं का भरोसा आयोग पर बना रहे।

जमींदारी उन्मूलन से राजस्व संहिता तक:कितना बदला प्रशासन?

—अखिल कुमार यादव—

उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन की कहानी केवल कानूनों की संख्या, धाराओं और सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था बदलने की कहानी नहीं है। यह उस किसान की कहानी है जिसकी जमीन कभी जमींदारी व्यवस्था के बीच उसके अधिकार का प्रश्न थी, फिर भूमिधरी अधिकारों का विषय बनी, और आज डिजिटल खतौनी, ऑनलाइन नामांतरण, कंप्यूटरीकृत राजस्व न्यायालय और ऑनलाइन पैमाइश की व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद भी एक सवाल आज उतना ही महत्वपूर्ण हैकृक्या राजस्व व्यवस्था वास्तव में उतनी सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकी है, जितनी इसकी कल्पना कानून बनाते समय की गई थी?

आज इस सवाल को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को तीन बड़े पड़ावों में देखना होगाकृ पहला, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950य दूसरा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006य और तीसरा, वर्तमान डिजिटल राजस्व प्रशासन। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमि सुधार कदम जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे यूपी एक्ट नंबर 1 ऑफ 1951 के रूप में प्रकाशित किया गया, का मूल उद्देश्य राज्य और खेती करने वाले व्यक्ति के बीच मौजूद मध्यस्थ जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना तथा उसके बाद भूमि–अधिकारों की नई व्यवस्था करना था। अधिनियम में धारा 1 से लेकर धारा 344 तक का विस्तृत कानूनी ढांचा था और इसके साथ अनेक अनुसूचियां भी थीं। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह केवल भू–राजस्व वसूली का कानून नहीं था। इसने भूमि पर अधिकार, जमींदारी के उन्मूलन, राज्य में संपत्तियों के निहित होने, काश्तकारों की स्थिति, भूमिधरी अधिकार, ग्राम सभा की भूमि, बेदखली, मुआवजा और राजस्व न्याय जैसी अनेक व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे में रखा। यानी 1950 का कानून मूलतः भूमि सुधार और भूमि–अधिकारों के पुनर्गठन का कानून था।

लेकिन समय के साथ उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधों की जटिलता बढ़ती गई। जमीन के उत्तराधिकार, बंटवारे, नामांतरण, सीमांकन, कब्जे, ग्राम समाज की भूमि, कृषि से गैर–कृषि उपयोग, पट्टे, भूमिधरी अधिकार और राजस्व न्यायालयों से संबंधित विषयों के लिए अलग–अलग कानून और संशोधन जुड़ते गए। पुराने कानून में समय–समय पर इतने संशोधन हुए कि मूल कानून और वर्तमान प्रशासनिक जरूरतों के बीच दूरी बढ़ने लगी। यहीं से एक नए और समेकित राजस्व कानून की आवश्यकता महसूस हुई। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 इसी आवश्यकता की परिणति थी। इसका उद्देश्य राज्य में भूमि–धारण और भू–राजस्व से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना था। राजस्व संहिता में कुल 234 क्रमांकित धाराओं का ढांचा है और इसे 16 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। अंतिम अध्याय में धारा 230 से 234 तक निरसन, लंबित कार्यवाहियों, कठिनाइयों को दूर करने, नियम और विनियम की व्यवस्था की गई है।

इस तुलना को यदि सरल भाषा में समझें तो 1950 के कानून का विस्तार धारा 344 तक था, जबकि नई राजस्व संहिता का मूल ढांचा धारा 234 तक है। लेकिन केवल यह कहना कि 344 धाराओं से घटकर 234 धाराएं हो गईं, अपने आप में सुधार का प्रमाण नहीं है। कानून की गुणवत्ता उसकी धाराओं की संख्या से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वह नागरिक के अधिकार और प्रशासनिक प्रक्रिया को कितना स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। राजस्व संहिता की एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने पुराने कई कानूनों को समाप्त कर एक समेकित व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। संहिता की धारा 230 के तहत प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों को निरसित किया गया। साथ ही पुराने कानूनों के अंतर्गत किए गए वैध कार्यों, तैयार अभिलेखों, अधिकारों और दायित्वों को संक्रमणकाल में सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई। यह परिवर्तन केवल कानूनी भाषा का परिवर्तन नहीं था। इसका उद्देश्य था कि किसान और राजस्व अधिकारी को जमीन से संबंधित मामलों में अलग–अलग पुराने कानूनों के जंगल में न भटकना पड़े। लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्व संहिता का नाम 2006 का है, पर इसका अधिकांश हिस्सा 11 फरवरी, 2016 से लागू हुआ। कुछ धाराएं, जिनमें धारा 1 और 4 से 19 तथा 233 और 234 शामिल थीं, 18 दिसंबर, 2015 से लागू की गईं, जबकि शेष प्रावधान 11 फरवरी, 2016 से प्रभावी हुए। इसलिए राजस्व संहिता के वास्तविक प्रशासनिक प्रभाव का आकलन 2016 के बाद की व्यवस्था को देखकर करना अधिक उचित है।

राजस्व संहिता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राजस्व प्रशासन को केवल भूमि–अधिकार तक सीमित नहीं रखा बल्कि भूमि रिकॉर्ड, सीमांकन, नामांतरण, उत्तराधिकार, गैर–कृषि उपयोग और राजस्व न्याय की प्रक्रियाओं को भी एक व्यवस्थित ढांचे में रखा। उदाहरण के लिए धारा 24 सीमाओं और सीमा–चिह्न से संबंधित विवादों के लिए महत्वपूर्ण है। आज इसी धारा के अंतर्गत पैमाइश संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ी हुई दिखाई देती है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी आरसीसीएमएस पर धारा 34 और धारा 80 सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। धारा 34 नामांतरण की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। जमीन बिकने, हस्तांतरित होने या अधिकार में परिवर्तन होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया किसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह उत्तराधिकार अथवा वरासत की प्रक्रिया भी ग्रामीण परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। धारा 80 कृषि भूमि के गैर–कृषि उपयोग से संबंधित व्यवस्था के कारण महत्वपूर्ण है। आज जब गांवों के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, तब यह प्रावधान भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्व संहिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू धारा 233 और 234 है। धारा 233 सरकार को संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है, जिसमें सीमांकन, नक्शे और अभिलेख तैयार करने, उत्तराधिकार और हस्तांतरण की रिपोर्टिंग तथा गांव के अभिलेखों में संशोधन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। धारा 234 राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया तथा भूमि अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित विनियम बनाने की व्यवस्था करती है। यानी 1950 का कानून जहां मुख्यतः भूमि संबंधों को पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक उद्देश्य से बना था, वहीं 2006 की संहिता ने भूमि प्रशासन को एकीकृत करने की कोशिश की।

इसके बाद तीसरा बड़ा परिवर्तन आयाकृडिजिटल राजस्व प्रशासन। आज किसान घर बैठे खतौनी देख सकता है। राजस्व न्यायालय में चल रहे मुकदमे की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। आदेश और अगली तारीख की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। धारा 34 और धारा 80 जैसे मामलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। आरसीसीएमएस का घोषित उद्देश्य ही राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाना तथा वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम जनता को मुकदमों की तारीख, आदेश और कार्यवाही की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। यह निश्चित रूप से उस दौर से बड़ा परिवर्तन है जब किसान को एक साधारण खतौनी या मुकदमे की स्थिति जानने के लिए तहसील कार्यालय की खिड़की तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन यहीं से राजस्व सुधार की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या डिजिटल रिकॉर्ड का अर्थ सही रिकॉर्ड भी है?

यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन खतौनी उपलब्ध होना और खतौनी में दर्ज तथ्य का जमीन पर सही होना दो अलग–अलग बातें हैं। यदि रिकॉर्ड में नाम गलत है, क्षेत्रफल गलत है, गाटा संख्या गलत है, नक्शा और मौके की स्थिति अलग है या उत्तराधिकारी का नाम दर्ज नहीं है, तो केवल रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर देने से किसान की समस्या समाप्त नहीं होती। राजस्व सुधार की असली कसौटी इसलिए तीन स्तरों पर होनी चाहिएकृरिकॉर्ड की शुद्धता, प्रक्रिया की गति और न्याय की समयबद्धता। रिकॉर्ड की शुद्धता का सवाल आज भी महत्वपूर्ण है। पुराने कागजी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन यदि डिजिटल रिकॉर्ड में पुरानी गलती चली आती है तो तकनीक उस गलती को समाप्त नहीं करतीय वह उसे केवल डिजिटल रूप दे देती है। इसी तरह नामांतरण ऑनलाइन हो जाने से प्रक्रिया आसान हुई है, लेकिन यदि विवादित नामांतरण वर्षों तक न्यायालय में चलता रहे तो किसान की समस्या समाप्त नहीं होती। पैमाइश का मामला भी यही बताता है। खेत की मेड़, रास्ता, नाली, चक और पड़ोसी के कब्जे का विवाद ग्रामीण जीवन में अत्यंत संवेदनशील विषय है। कानून में सीमांकन की प्रक्रिया होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि निर्धारित प्रक्रिया के बाद जमीन पर वास्तविक सीमांकन हो और उसका रिकॉर्ड भी उसी के अनुरूप अद्यतन हो। राजस्व सुधार का सबसे कठिन मोर्चा राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक आरसीसीएमएस डैशबोर्ड पर वर्तमान में लगभग 30.16 मिलियन राजस्व वाद पोर्टल पर दर्ज, लगभग 1.16 मिलियन विचाराधीन और लगभग 45,563 वाद पांच वर्ष से अधिक पुराने दिख रहे हैं। यह आंकड़ा पोर्टल की वर्तमान स्थिति का है और समय के साथ बदलता रहता है। विभिन्न स्तरों को जोड़ने वाले आधिकारिक डैशबोर्ड में राजस्व परिषद से लेकर नायब तहसीलदार तक के न्यायालयों की स्थिति दिखाई जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। लाखों मुकदमों का निस्तारण होना निश्चित रूप से प्रशासनिक गतिविधि का संकेत है, लेकिन लंबित मामलों की मौजूदगी यह बताती है कि डिजिटल न्यायिक सूचना और वास्तविक समयबद्ध न्याय एक ही चीज नहीं हैं। यही राजस्व सुधार का अगला चरण होना चाहिए। आज किसान को केवल यह नहीं चाहिए कि उसका मुकदमा ऑनलाइन दिखाई दे। उसे यह भी चाहिए कि मुकदमा अनावश्यक रूप से वर्षों तक न चले। उसे केवल ऑनलाइन खतौनी नहीं चाहिएय उसे सही खतौनी चाहिए। उसे केवल ऑनलाइन नामांतरण आवेदन नहीं चाहिएय उसे समयबद्ध नामांतरण चाहिए। उसे केवल पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं चाहिएय उसे जमीन पर वास्तविक और निष्पक्ष पैमाइश चाहिए।

इसीलिए अब राजस्व सुधार की दिशा ष्कंप्यूटरीकरणष से ष्जवाबदेह डिजिटल राजस्व न्यायष की ओर बढ़नी चाहिए। इसमें सबसे पहले भूमि रिकॉर्ड की नियमित शुद्धता–जांच होनी चाहिए। नक्शे और खतौनी का वास्तविक भू–भाग से मिलान कराया जाना चाहिए। सीमांकन में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ना चाहिए। उत्तराधिकार के मामलों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए कि मृत्यु का पंजीकरण होने के बाद संबंधित भूमि रिकॉर्ड में उत्तराधिकार की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो सके, हालांकि अंतिम प्रविष्टि आवश्यक वैधानिक जांच के बाद ही हो। इसी तरह नामांतरण, पैमाइश और वरासत के लिए स्पष्ट समयसीमा और प्रत्येक चरण की ऑनलाइन निगरानी होनी चाहिए। जहां देरी हो, वहां केवल आवेदक को अगली तारीख न मिले बल्कि जिम्मेदारी का रिकॉर्ड भी बने। राजस्व न्यायालयों में पुराने मामलों के लिए अलग निस्तारण अभियान चलाया जा सकता है। पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को अलग श्रेणी में लेकर उनकी प्रगति की सार्वजनिक निगरानी की जा सकती है। आरसीसीएमएस स्वयं धारा–वार लंबित वादों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखता हैय इसका उपयोग केवल आंकड़े दिखाने के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए भी किया जा सकता है।

महिलाओं के भूमि अधिकार भी राजस्व सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उत्तराधिकार कानून में अधिकार मिल जाना पर्याप्त नहीं हैय राजस्व रिकॉर्ड में वह अधिकार समय पर दर्ज होना भी उतना ही जरूरी है। इसी तरह ग्राम पंचायत, तालाब, चरागाह, सार्वजनिक रास्ते और अन्य सामुदायिक भूमि के रिकॉर्ड को भी शुद्ध रखना जरूरी है, क्योंकि इन जमीनों से जुड़े विवाद निजी भूमि विवादों से अलग सामाजिक प्रभाव पैदा करते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि राजस्व प्रशासन केवल तहसील की समस्या नहीं है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त और राजस्व परिषद तक पूरी श्रृंखला की भूमिका है। किसी एक स्तर पर रिकॉर्ड की गलती दूसरे स्तर पर विवाद पैदा कर सकती है और अंततः वही विवाद न्यायालय में पहुंच सकता है। इसलिए राजस्व सुधार का अगला मॉडल केवल ष्नई धारा जोड़ोष नहीं होना चाहिए, बल्कि ष्गलती होने से पहले रोकिए, गलती हो तो जल्दी सुधारिए और विवाद हो तो समयबद्ध निर्णय दीजिए' होना चाहिए। 1950 के कानून ने एक ऐतिहासिक प्रश्न का उत्तर दिया थाकृजमींदारी व्यवस्था समाप्त करके भूमि संबंधों को किस नए ढांचे में रखा जाए?

राजस्व संहिता, 2006 ने दूसरा प्रश्न उठायाकृभूमि और भू–राजस्व से जुड़े अनेक कानूनों को एक समेकित संहिता में कैसे लाया जाए? डिजिटल राजस्व व्यवस्था ने तीसरा सवाल सामने रखाकृराजस्व रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से आम नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए? अब 2026 के दौर में चौथा सवाल सामने हैकृक्या किसान को समयबद्ध, सही और जवाबदेह राजस्व न्याय मिल रहा है?

यही वह प्रश्न है जो जमींदारी उन्मूलन से राजस्व संहिता तक की लगभग सात दशक लंबी यात्रा का वास्तविक मूल्यांकन करेगा। क्योंकि किसान के लिए कानून की सफलता उसकी धाराओं की संख्या में नहीं है। 344 धाराओं वाला कानून हो या 234 धाराओं वाली संहिताकृकिसान के लिए असली कानून वही है जो उसकी जमीन का रिकॉर्ड सही रखे, उसकी वरासत समय पर दर्ज करे, उसकी जमीन की पैमाइश निष्पक्ष रूप से कराए और उसके विवाद का फैसला अनावश्यक देरी के बिना कराए। 1950 में उत्तर प्रदेश ने भूमि व्यवस्था को बदलने का साहस किया। 2006 की संहिता ने पुराने कानूनों को समेटने का प्रयास किया। 2016 के बाद डिजिटल व्यवस्था ने राजस्व प्रशासन को तकनीक से जोड़ा। लेकिन अब सुधार की अगली मंजिल केवल कानून बदलना नहीं, कानून को जमीन पर समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है।

यानी राजस्व सुधार की यात्रा जमींदारी उन्मूलन से शुरू होकर राजस्व संहिता तक पहुंची हैय अब उसे ष्सही रिकॉर्ड और समयबद्ध न्यायष तक पहुंचना बाकी है।

युवाओं के हाथ में डिग्री, रोजगार की तलाश

—प्रहलाद गुप्ता—

देश की युवा आबादी को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं। उनके हाथ में डिग्री होती है, आंखों में बेहतर भविष्य के सपने होते हैं और परिवार को उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता तो यही उम्मीद धीरे–धीरे चिंता में बदलने लगती है।

आज रोजगार का सवाल केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि युवाओं की शिक्षा और बाजार की जरूरतों के बीच कितना तालमेल है। कई युवा वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सीमित अवसरों के कारण उनका इंतजार लंबा होता जाता है। दूसरी ओर कई क्षेत्रों में योग्य लोगों की जरूरत होने के बावजूद आवश्यक कौशल वाले युवाओं की कमी दिखाई देती है।इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कर डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए। युवाओं को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वे बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों के अनुसार अपने आपको तैयार कर सकें। पढ़ाई के साथ कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी जानकारी भी जरूरी है। सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसलिए निजी क्षेत्र, छोटे उद्योग, स्थानीय कारोबार और स्वरोजगार के अवसरों को भी मजबूत करना होगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो युवाओं को नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह चुनौती और महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां बड़ी संख्या में युवा हर वर्ष रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। यदि इन्हें स्थानीय स्तर पर काम और आगे बढ़ने के अवसर मिलें तो इसका लाभ केवल युवाओं को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।द्य रोजगार केवल आमदनी का साधन नहीं है। यह युवा को आत्मविश्वास, सम्मान और अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा का एहसास भी देता है। लंबे समय तक बेरोजगारी युवा मन में निराशा पैदा कर सकती है। इसलिए रोजगार के आंकड़ों के साथ यह भी देखना जरूरी है कि युवाओं को किस तरह का काम मिल रहा है, उसकी आय कितनी है और उसमें आगे बढ़ने की कितनी संभावना है।

आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें डिग्री और रोजगार के बीच की दूरी कम हो। शिक्षा संस्थानों, सरकार और उद्योग जगत को मिलकर यह समझना होगा कि आने वाले वर्षों में किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को उसी दिशा में तैयार किया जाए।

देश के युवाओं के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है और आगे बढ़ने की इच्छा भी है। जरूरत केवल उन्हें सही अवसर देने की है। युवा यदि रोजगार की तलाश में वर्षों भटकने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकें, तो यही युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। डिग्री हाथ में होना शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली चुनौती यह है कि उस डिग्री को सम्मानजनक रोजगार और आत्मनिर्भरता से कैसे जोड़ा जाए। यही सवाल आज की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। लेकिन रोजगार की समस्या का समाधान केवल नई नौकरियां पैदा करने से नहीं होगा। जरूरी यह भी है कि रोजगार की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और युवाओं के लिए आसान हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवा वर्षों तक परिणाम और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करते हैं। परीक्षा की तैयारी में लगने वाला समय, आवेदन की फीस, यात्रा और दूसरी लागत परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी युवाओं की परेशानी को और बढ़ाती है।

दूसरी बड़ी चुनौती रोजगार की गुणवत्ता की है। किसी युवा को काम मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि उसे उसके काम के अनुरूप सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है या नहीं।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल

—रोहित माहेश्वरी—

भारत के चुनाव आयोग को अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अनियमितताओं के नए आरोपों की एक श्रृंखला के बाद विश्वसनीयता के एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक संस्थानों में से एक, तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं और इसमें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आयुक्त के रूप में शामिल हैं। यह ताजा विवाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में, मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार से उनके दो सहयोगियों ने वोटर डेटाबेस की सत्यनिष्ठा, नए मतदाताओं के नामांकन के तरीके में बदलाव और मतदाता सूची की सुरक्षा को लेकर बार–बार सवाल किए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर देश का विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है।

ताजा खुलासों ने विपक्षी दलों और आलोचकों को भी नया बल प्रदान किया है, जो बार–बार दावा करते रहे हैं कि एसआईआर का इस्तेमाल भाजपा के लाभ के लिए उनके वोटरों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है और भारत में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहे हैं। हालांकि, चुनाव हारने पर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला पुराना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का चुनाव आयोग विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जिसकी तपिश भारतीय लोकतंत्र की साख पर भी पड़ती है। निस्संदेह, चुनाव आयोग का दायित्व लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव कराना और नागरिकों के वोट देने के महत्वपूर्ण अधिकार की रक्षा करना होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को विवादित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' यानी एसआईआर से जुड़ी विसंगतियों ने भारी ठेस पहुंचाई है। हाल ही में दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की पड़ताल में पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्तूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम चौदह बार उन फैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी में लाए बगैर लिये गए थे।

सूत्रों के मुताबिक इन दो चुनाव आयुक्तों की चिंताओं में फॉर्म–6 में बदलाव, वोटर लिस्ट डेटाबेस का सेंट्रलाइजेशन, फील्ड अधिकारियों की इस तक सीमित पहुंच और वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया शामिल थी। निस्संदेह, इस प्रकरण से मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति असहज हो गई है। इसके बाद अक्सर चुनाव आयोग पर हमलावर रहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहा है। इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने और कथित चुनावी अनियमितताओं के विरोध में बड़े पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान किया है। विरोध आंदोलन के तहत आगामी दो से आठ अक्टूबर तक विपक्षी पार्टियां देशभर में जिला स्तरीय श्लोकतंत्र बचाओ मार्चश निकालकर चुनावी धांधलियों के प्रति जागरूकता फैलाएंगी। गठबंधन के सभी सांसद छह अक्टूबर को दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे।

भाजपा नेताओं का तर्क है कि जब विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं, तब उन्हें ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन हारने पर वे इन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उन्हीं ईवीएम और प्रक्रियाओं से कई राज्यों में सरकारें बना चुके हैं, फिर भी हार मिलने पर इन्हें श्ब्लैक बॉक्सश या पक्षपाती करार देते हैं।

रामेश्वर तिवारी हत्याकांडः एसओ सहित चार पुलिसकर्मी निलंबित पीड़ित परिवार से डीआईजी बोले– कार्रवाई नजीर बनेगी

संवाददाता–देवरिया। जिले के लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा पहुंचे डीआईजी एस चनप्पा ने रामेश्वर तिवारी के परिजनों से मिल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परिजनों ने हल्का दारोगा पर लापरवाही का आरोप आरोप लगा कार्रवाई की मांग की। इस पर डीआईजी ने प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह हल्का दरोगा राममूरत बीट सिपाही चंद्रभान भारती, प्रीतम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस लाइन में तैनात निर्भय कुमार को लार थाने की कमान सौंप दी है।

डीआईजी ने आरोपी के घर पहुंच मौके का निरीक्षण किया। परिजनों ने कहा हमारे परिवार के दो लोगों की हत्या हो चुकी है। वहीं एक चालक की भी हत्या कर दी गई। आरोपियों पर एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर डीआईजी ने कहा कि कार्रवाई नजीर बनेगी। किसी भी हाल में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। एहतियात के तौर पर पीएसी सहित कई थाने की फोर्स लगाई गई है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई है। पूरी रात टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन अभी तक आरोपी हत्थे नहीं चढ़ सके हैं।पत्नी अमृता की शिकायत पर गांव के ही संजय तिवारी, दीपक तिवारी, प्रांजल तिवारी, अभिनीत, आदित्य, निखिल तिवारी व दस अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछ ताछ कर रही है।

लार क्षेत्र के भीखम छपरा गांव में सड़क पर ब्रेकर बनवाने से नाराज विरोधियों ने बृहस्पतिवार की शाम करीब पांच बजे आरएसएस कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी (55) की लाठी–डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वारदात के पीछे वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। भीखम छपरा गांव निवासी रामेश्वर तिवारी आरएसएस के कार्यकर्ता थे।

चुनावी कार्यक्रम में सपा–भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, धक्का–मुक्की, पीएसी तैनात

संवाददाता–बहराइच। महसी विधानसभा क्षेत्र में जनता का चुनावी मूड जानने पहुंची निजी चौनल की टीम के कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार दोपहर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने–सामने आ गए और उनके बीच खींचतान व धक्का–मुक्की शुरू हो गई। हंगामे से कार्यक्रम स्थल पर अफरा–तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। मामला हरदी थाना क्षेत्र के रमपुरवा चौराहे का है। एक निजी चौनल की टीम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानने के लिए कार्यक्रम कर रही थी। इसी दौरान किसी मुद्दे को लेकर सपा और भाजपा समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक–दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान धक्का–मुक्की और खींचतान होने लगी। हंगामा बढ़ने पर कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने दोनों पक्षों के बीच पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि फोर्स तैनात है, पुलिस मामले की जानकारी एकत्र की जा रही है।

चौरीचौरा में खेत देखने गए किसान की डूबने से मौत

संवाददाता–देवरिया। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के सिवान में शुक्रवार को धान का खेत देखने गए किसान की पानी में डूबने से मौत हो गई। बघाड़ खास गांव निवासी लालबिहारी साहनी (58) का शव उनके खेत में भरे पानी में मिला। आशंका है कि खेत में अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद वह पानी में डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार लालबिहारी साहनी शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे घर से भोजन करने के बाद खेत देखने के लिए निकले थे। करीब दो घंटे बाद भी वह घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। परिजन उन्हें खोजते हुए खेत की ओर गए। वहां लालबिहारी खेत में भरे पानी में मृत अवस्था में मिले। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथमदृष्ट्या आशंका है कि किसान खेत में अचानक बेहोश होकर गिर गए होंगे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान में बूथ स्तर तक जाएगी सपा –जिलाध्यक्ष

संवाददाता–महराजगंज। वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को भाजपा व चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिला कार्यालय पर प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से विपक्षी विचारधारा से जुड़े मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा के लिए पार्टी बूथ स्तर तक अभियान चलाएगी। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महराजगंज में 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल के उपचुनावों के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बिना नोटिस काटे गए। उन्होंने कहा कि सपा की ओर से इस मामले में प्रमाण सहित चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का बूथवार सत्यापन कराने और कटे नाम तत्काल जुड़वाने की मांग की। एसआईआर को लेकर भी सपा ने सरकार पर निशाना साधा।जिलाध्यक्ष ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष भूमिका निभाने की मांग की। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद–फरोख्त का आरोप लगाया। कहा कि 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर तक जिले के प्रत्येक बूथ पर वोट बचाओ चौपाल लगाई जाएगी। मतदान के दौरान सीसीटीवी व वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराने की मांग भी की गई। इस दौरान श्रवण पटेल, अमरजीत साहनी, विजय यादव, विजय जायसवाल, अशोक यादव, अमरनाथ यादव, कैलाश प्रजापति, राजकुमार, बबलू भारती आदि मौजूद रहे।

बर्खास्त सिपाही साथियों के साथ चला रहे थे वसूली सिंडिकेट एनकाउंटर और जेल भेजने की देते धमकी, चार गिरफ्तार

संवाददाता–बहराइच। जिले के हरदी थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर दुकानदारों को गांजा रखने के आरोप में जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर धन उगाही के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले में दो पूर्व पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 7.795 किलो गांजा, तमंचा, दो कारतूस, पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी, पी–कैप, पुलिस बैज, फर्जी नंबर प्लेट और लाल–नीली बत्ती लगी कार बरामद हुई है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों पूर्व पुलिसकर्मी पुलिस का भेष धारणकर दुकानदारों और अन्य लोगों से वसूली करते थे। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि लाल–नीली बत्ती और सरकारी नंबर लिखा वाहन राजी चौराहे से दो लोगों को जबरन बैठाकर महसी की ओर ले जा रहा है। वाहन को सिंगिया नसीरपुर गांव के पास सिकंदरपुर जाने वाले बंधे पर रोककर तलाशी ली गई। वाहन चालक उपनिरीक्षक की वर्दी में था। पुलिस ने उससे विभागीय परिचय पत्र और वाहन के वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जांच में वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली।

वाहन में पीछे बैठे दोनों लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राजी चौराहे से असलहा दिखाकर जबरन वाहन में बैठाया गया है। आरोप है कि दोनों को गांजा रखने के आरोप में जेल भेजने और एनकाउंटर करने की धमकी देकर रुपये मांगे जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वाहन और चारों आरोपियों की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक, वर्दी पहने व्यक्ति ने अपना नाम समर बहादुर सिंह बताया। पूछताछ में उसने बताया कि वह वर्ष 1997 में 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में भर्ती हुआ था। वर्ष 2019 में 35वीं वाहिनी लखनऊ में तैनाती के दौरान लड़ाई–झगड़े और नियम विरुद्ध आचरण के कारण उसे जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया था। दूसरे आरोपी श्रीप्रकाश द्विवेदी उर्फ प्रकाश दूबे को पुलिस ने वर्ष 2006 बैच का बर्खास्त सिपाही बताया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे पुलिसकर्मी का भेष धारण कर दुकानदारों और अन्य लोगों को गांजा रखने या बेचने के आरोप में जेल भेजने का भय दिखाकर धन उगाही करते थे। जेल में रहने के दौरान उन्हें राजी चौराहे की पान और परचून की दुकानों पर गांजे वाली सिगरेट बिकने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर दोनों दुकानदारों को जबरन वाहन में बैठाकर वसूली का प्रयास किया जा रहा था।

वाहन में मौजूद मूले अवस्थी उर्फ अवधेश अवस्थी और वीरेंद्र उर्फ छोटू ने पूछताछ में अपने–अपने दुकानों पर गांजे की छोटी–छोटी पुड़िया बनाकर बेचने की बात बताई। उनकी निशानदेही और तलाशी के दौरान मूले अवस्थी के पास से 51 ग्राम और उसकी निशानदेही पर 3.280 किलो गांजा बरामद हुआ। वीरेंद्र के पास से 94 ग्राम और उसकी निशानदेही पर 2.170 किलो गांजा बरामद किया गया। वाहन से 2.200 किलो गांजा बरामद हुआ। इस तरह कुल 7.795 किलो गांजा बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 8,270 रुपये नकद, छह एंड्रायड मोबाइल, उपनिरीक्षक की वर्दी, पी–कैप, पुलिस बैज, प्लास, रिंच और दो फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की हैं। पुलिस ने रेनॉल्ट ट्राइबर कार को भी कब्जे में लिया है। चारों आरोपियों के खिलाफ हरदी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, श्रीप्रकाश द्विवेदी के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में आयुध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, डकैती, बरामदगी, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं। समर बहादुर सिंह के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में दो मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं मूले अवस्थी के खिलाफ हरदी थाने में एक और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज बताया गया है।

सात साल की अनामिका ने बिना थके बिना रुके पूरी की 30 किमी की दौड़

संवाददाता–गोण्डा। गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोंडा जिले में गांधी जयंती पर सात साल की अनामिका ने 30 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर गांधी पार्क पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। बिना थके और बिना रुके अनामिका ने पौने तीन घंटे में दौड़ पूरी की। गांधी पार्क पहुंचने पर आईजी अशोक शुक्ला ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया। अनामिका के स्वागत के लिए गांधी पार्क में बड़ी संख्या में लोग जुटे। अनामिका ने वर्ष 2025 में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इस बार उसने अपनी दौड़ की दूरी बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दी। गांधी जयंती के मौके पर अनामिका की दौड़ के साथ बड़ी संख्या में लोग भी दौड़े। गांधी पार्क में पहुंचने के बाद लोगों ने अनामिका का उत्साह बढ़ाया।

जिले के इटियाथोक के प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा की कक्षा दो की सात वर्षीय छात्रा अनामिका मिश्रा ने शुक्रवार सुबह छह बजे विद्यालय से 30 किलोमीटर लंबी दौड़ शुरू की। अनामिका के दौड़ शुरू करते ही विद्यालय के शिक्षकों, ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने उसका उत्साह बढ़ाया। रास्ते में प्राथमिक विद्यालय चुरिहारपुर और पारासराय के छात्रों ने अनामिका का फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं, ग्रामीण भी जगह–जगह सड़क किनारे खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। छात्रा के साथ पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी मौजूद रही।

नवजात को धान के खेत में छोड़ा,मां और नानी गिरफ्तार

संवाददाता–बलरामपुर। श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र में धान के खेत में जिंदगी और मौत के बीच मिली नवजात बच्ची के मामले में पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, लोक–लाज के डर से बच्ची को मरने के लिए सुनसान खेत में छोड़ दिया गया था। मामले में बच्ची की 22 वर्षीय मां और 48 वर्षीय नानी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस घटना में कथित रूप से शामिल रिश्तेदार साजन, जिसे बच्ची का बहनोई बताया जा रहा है, की तलाश कर रही है।

एसपी ने शुक्रवार दोपहर 2रू30 बजे बताया कि घटना 17 सितंबर की सुबह करीब 5रू25 बजे की है। ग्राम किठुरा के धान के खेत में सफेद कपड़े में लिपटी करीब एक दिन की नवजात बच्ची पड़ी मिली थी। उसकी हालत बेहद खराब थी और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था।

नवजात के खेत में पड़े होने की सूचना मिलते ही च्ट्ट–5455 मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, कमांडर कांस्टेबल सुशान्त तिवारी और पायलट होमगार्ड विजय सिंह ने बिना देर किए धान के खेत से बच्ची को बाहर निकाला। इसके बाद उसे सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर के महिला प्रसव वार्ड में बच्ची का उपचार कराया गया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। वर्तमान में बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है।

मामले में ग्राम चौकीदार राममिलन पुत्र रामदास की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर के मुताबिक, गांव की एक युवती कुछ समय से गर्भवती थी और करीब एक–दो महीने से गांव में नहीं रह रही थी। 16 सितंबर की रात कुछ ग्रामीणों ने युवती और उसकी मां को नवजात के साथ घर जाते देखा था। ग्रामीणों के पूछने पर दोनों ने बच्चे के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद युवती गर्भवती नजर नहीं आई और उसके घर में भी कोई नवजात बच्चा नहीं मिला। इसी आधार पर ग्रामीणों को आशंका हुई कि धान के खेत में मिली बच्ची उसी युवती की है।

पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरुआत में दोनों टालमटोल करती रहीं। पुलिस का दावा है कि कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने घटना स्वीकार कर ली। पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि लोक–लाज के डर से नवजात को खेत में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, युवती का अपने ही रिश्तेदार से संबंध था। इसी घटनाक्रम में रिश्तेदार साजन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तलाश कर रही है।

पुलिस ने नवजात की मां उम्र करीब 22 वर्ष और नानी उम्र करीब 48 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामधारी दिनकर, उपनिरीक्षक आदित्य कुमार, महिला कांस्टेबल आरती सिंह, पुष्पा देवी और शिवांगी मौर्या की टीम ने की।

गांधी जयंती पर पूर्व सैनिक ने की आत्मदाह की कोशिश, सीएम योगी से चार बार कर चुके फरियाद

संवाददाता–देवरिया। भूमि विवाद के मामले का निस्तारण नहीं होने से परेशान एक पूर्व सैनिक ने शुक्रवार को गांधी जयंती पर देवरिया कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया जिससे हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूर्व सैनिक को पकड़ कर आत्मदाह करने से रोका। पीड़ित ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी चार बार वो उनकी परेशानी का हल निकालने की फरियाद कर चुके हैं। आत्मदाह की सूचना पर पहुंचे एडीएम प्रशासन प्रेमनारायण सिंह ने पूर्व सैनिक को समझा कर जिलाधिकारी के पास ले गए।

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने पूर्व सैनिक की समस्याओं को सुनने के बाद एसडीएम भाटपाररानी को फोन कर समस्या का तत्काल निस्तारण करने को कहा। इसके बाद पूर्व सैनिक को पुलिस सुरक्षा में उनके घर भेज दिया गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार खामपार थाना क्षेत्र के भिंगारी बाजार के रहने वाले सत्येंद्र कुमार शाही सेवानिवृत्त सैनिक हैं। उनका आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि पर भू–माफिया व अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने वालो में टाप–टेन की सूची में शामिल एक व्यक्ति भी शामिल हैं। उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि चार बार मुख्यमंत्री के जनता दर्शन गोरखनाथ मंदिर में फरियाद किया।

कहा जा रहा है कि सीएम योगी से मिलने के बाद हर बार देवरिया जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश तो दिए गए, लेकिन मिलीभगत के चलते प्रार्थना पत्र को हर बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई बार पैमाइश भी हुई, लेकिन न्याय नहीं दिलाया गया। इससे परेशान होकर उन्होंने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। इसकी सूचना उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से मुख्यमंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों को भी भेजी थी।

शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे वे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने ऊपर तेल उड़ेल लिया। यह देख ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ कर गैलेन छीन लिया। सूचना मिलते ही एडीएम प्रशासन प्रेमनारायण सिंह मौके पर पहुंचे और पूर्व सैनिक को समझा कर जिलाधिकारी के पास ले गए।

एडीएम प्रशासन प्रेमनारायण सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने पूरा प्रकरण सुनने के बाद भाटपाररानी के एसडीएम दीपराज सिंह को फोन पर मामले का तत्काल निस्तारित कराने का निर्देश दिया। इसके बाद पूर्व सैनिक को संतुष्ट करते हुए पुलिस की सुरक्षा में उनके घर भेज दिया गया। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व सैनिक को आश्वासन दिया गया है कि उनकी परेशानी का निस्तारण किया जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों की सुनी समस्या

संवाददाता–महराजगंज। आधारशिला वृद्धाश्रम गणेशपुर फरेंदा में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम प्रेमशंकर पांडेय, विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश जायसवाल व बीडीओ अतुल कुमार ने बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। एसडीएम ने कहा कि वृद्ध जनों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कहा कि खुशी होती है कि यहां वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की अच्छे से सेवा हो रही है। इस दैरान जिला युवा अधिकारी प्रखर शर्मा, तहसीलदार फरेंदा वशिष्ठ वर्मा, समाजसेवी देवी शरण दुबे, परमात्मा विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

अजगर ने युवक की गर्दन कसकर मार डाला

संवाददाता–कुशीनगर। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बड़वाछापर गांव में गुरुवार को नहर में मछली पकड़ने गए युवक पर अजगर ने हमला कर दिया। युवक नीचे झुककर मछली पकड़ने की तैयारी में था, तभी अजगर ने उसकी गर्दन दबोच ली और पूरे शरीर को लपेटने के बाद कसकर मार डाला। आसपास के लोग जब तक पहुंचे, अजगर झाड़ियों में भाग गया था। ग्रामीण युवक को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजगर को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाई।

बड़वाछापर निवासी अनिरुद्ध राजभर का 21 वर्षीय पुत्र किशन राजभर गुरुवार सुबह गांव के पीछे स्थित नहर में मछली मारने गया था। वह प्रेमपुर जवाह और महुई माइनर को जोड़ने वाले साइफन के समीप पहुंचा। किनारे खड़े होकर नहर में मछली पकड़ने के लिए झुका ही था कि तभी बांध की ओर से एक विशाल अजगर रेंगते हुए पीछे से आया और किशन की गर्दन को जकड़ लिया। अजगर ने उसके शरीर को भी लपेट लिया और उसे लेकर साइफन के समीप पानी में गिर गया। अचानक हुए हमले से युवक संभल नहीं सका।

मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक किशन को छोड़कर अजगर झाड़ियों में जा चुका था। परिजन किशन को जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रामकोला एसओ चंद्रभान सिंह ने बताया किमौके पर पुलिस गई थी। घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों का एक समूह लाठी–डंडे लेकर आसपास की झाड़ियों में अजगर को खोजता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। लोगों को अजगर को लेकर सचेत कर दिया गया है।

कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बड़वाछापर गांव में गुरुवार को नहर में मछली पकड़ने पहुंचे किशन राजभर को एक अजगर ने गला कसकर मार डाला। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माता–पिता और अन्य परिजन दहाड़ें मारकर रोने लगे। पूरे गांव में मातम पसरा है।

किशन चार भाइयों में दूसरे नम्बर का था। घर पर रहकर पिता के साथ काम करता था। बड़ा भाई शिवम रोजी–रोटी के सिलसिले में बाहर है। दो छोटे भाई व दो बहन गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पिता मेहनत–मजदूरी करते हैं, जबकि मां गृहणी हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

खेल गतिविधियों को दें बढ़ावा, प्रतिभाओं को दें प्लेटफार्म -डीएम

संवाददाता–महराजगंज। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। बैठक में जनपद में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति से अधिकाधिक खेल संघों को जोड़ा जाए। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में सक्रिय सभी खेल संघों को समिति से जुड़ने के लिए सूचित करते हुए उनसे आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जाएं तथा नियमानुसार उन्हें समिति का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक खेल संघों की सहभागिता से खिलाड़ियों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप खेल सुविधाओं के विकास में भी सहायता मिलेगी।एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार को जिला एवं तहसील स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समितियों का चिटफंड सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकरण कराने को कहा। जिला युवा अधिकारी को जिलास्तर तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी को तहसील स्तर पर खेलों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कहा कि जनपद की युवा खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए बेहतर खेल सुविधाओं के विकास के साथ नियमित रूप से खेल प्रतियोगिताओं एवं स्पर्धाओं का आयोजन आवश्यक है।

चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने भरी हुंकार, एकजुट होने की अपील

संवाददाता–महराजगंज। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के देवघट्टी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई । साथ ही 2027 विधानसभा के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत आज विधानसभा के प्रति बूथ पर बूथ अध्यक्ष की मौजूदगी है। यह पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। कहा कि जिन महिलाओं का नाम सूची से काट दिया गया है, आने वाले अभियान में उनका नाम मतदाता सूची में डलवाने के लिए कांग्रेस एक अभियान चलाएगी।

पूर्व प्रदेश महासचिव त्रिभुवन मिश्रा ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार से वंचित कर रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही।पूर्व जिलाध्यक्ष झिनकू चौधरी ने कहा कि आज नौतनवा में जगह–जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। सम्मेलन में डॉ. रामनारायण चौरसिया, संतोष यादव, सदामोहन उपाध्याय, इसरार अहमद, मोहम्मद अमीन खान, प्रमोद पांडेय, निहाल इराकी, सुरेश मणि त्रिपाठी, अनिरुद्ध यादव, प्रमोद दुबे, समीउल्लाह खान, इंद्रेश चौधरी, सुरेश यादव, राधेश्याम, ओम प्रकाश पांडेय, गिले खान, विनोद सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, दिल्ली से दरभंगा जा रही बस ट्रेलर से भिड़ी, चार यात्रियों की मौत

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के भीषण हादसा हो गया। अम्बरपुर टोल प्लाजा के पास दिल्ली से दरभंगा जा रही एसी बस ओवरटेक करने के दौरान ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 40 फीट लंबी बस का बायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस सवार चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और घायल सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत–बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा–तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल और नगपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब बस आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान ट्रेलर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर बस के बाएं हिस्से में हुई, जिससे उस तरफ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। इसी वजह से उस ओर बैठे कई यात्री सुरक्षित बच गए।

हादसे में मृत चार यात्रियों में से एक की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सचिन कुमार बिहार निवासी थे । तीन अन्य मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है।

हादसे में घायल यात्रियों में तीन की पहचान हो गई है। इनमें सुमित मिश्रा (33), सुमित आनंद (40) और रिंकू कुमारी (45) शामिल हैं। तीनों बिहार के दरभंगा के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। एडिशनल एसपी ने हादसे में चार यात्रियों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ ही मृतकों की पहचान कराने में जुटी है।

सपा से चुनाव लड़ेंगे डॉ. संजयन, लखनऊ में सदस्यता ली

संवाददाता–गोरखपुर। पिछले लगभग 4 सालों से भाजपा में सक्रिय रहकर टिकट का दावा कर रहे डा. संजयन त्रिपाठी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद संजयन ने अपना दुख व्यक्त किया था। इसके बाद अपनी कार से बीजेपी का झंडा सार्वजनिक रूप से हटा दिया। अब लखनऊ में सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सूत्रों की मानें तो अब वह सपा से गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी होंगे। हालांकि सपा ने कमलेश यादव को टिकट दिया है लेकिन उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं किया है। डॉ. संजयन त्रिपाठी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। देवरिया जिले के मठलार डिग्री कॉलेज में वह हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। उनके करीबी रिश्तेदार भी स्कूलों की श्रृंखला का संचालन करते हैं। खुद शिक्षक होने और शैक्षणिक संस्थाओं का संचालक होने के नाते उन्हें मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। एडेड विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या अधिक है। डा. संजयन त्रिपाठी ने 2022 में भाजपा की सदस्यता ली थी। 2023 में गोरखपुर–फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने थे। वह टिकट के दावेदार थे लेकिन अंत समय में टिकट देवेंद्र प्रताप सिंह को मिला। टिकट की घोषणा होने के बाद डा. त्रिपाठी ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। इससे पहले वह दो बार यह चुनाव लड़ चुके थे और दोनों ही बार इसी प्रत्याशी के सामने रनर रहे थे। 2010 में पहली बार डा. त्रिपाठी यह चुनाव लड़े थे। उस समय देवेंद्र प्रताप सिंह सपा के कैंडिडेट थे। उन्होंने दूसरी बाद जीत हासल की थी। डा. संजयन त्रिपाठी दूसे स्थान पर रहे। अगले चुनाव में यानी 2016 में वह फिर निर्दल प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आए और इस बार भी वह दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने उनका समर्थन किया था। डा. संजयन को आश्वासन था कि उन्हें शिक्षक एमएलसी के लिए टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र से तीन बार शर्मा गुट से एमएलसी रहे ध्रुव त्रिपाठी को टिकट मिल गया। शर्मा गुट आमतौर पर किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ता था लेकिन निजी विद्यालयों के वोटरों की संख्या अधिक होने के बाद शर्मा गुट से तीन बार एमएलसी रहे ध्रुव त्रिपाठी ने राजनीतिक दल का हाथ थाम लिया।

न्यायालय कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शासन स्तर पर वर्षों से लंबित न्यायालय कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के निराकरण करवाने हेतु चलाए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन के तृतीय चरण में शाखा जनपद न्यायालय बस्ती के कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी एकजुटता और संघर्ष का सशक्त संदेश दिया।

तिरंगा यात्रा में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए सैकड़ों न्यायालय कर्मचारियों ने सहभागिता की तिरंगा यात्रा में संघ के मार्गदर्शक अवध बिहारी श्रीवास्तव ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद वंदे मातरम के उद्घोष के साथ शुरुआत की। यात्रा के माध्यम से कर्मचारियों ने शासन का ध्यान उन मांगों की ओर आकृष्ट कराया, जो वर्षों से शासन के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं और जिनका सीधा संबंध न्यायालय कर्मचारियों की सेवा–शर्तों, पदोन्नति और वेतनमान तथा कार्य–सुविधाओं से है। उवप्रव दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, बस्ती के अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने कहा कि न्यायालय कर्मचारी न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे माननीय न्यायाधीशों, विद्वान अधिवक्ताओं और वादकारियों के मध्य समन्वय की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु एवं प्रभावी बनाने में निरंतर योगदान देते हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा–संबंधी अनेक महत्वपूर्ण मांगें वर्षों से शासन स्तर पर लंबित होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय कर्मचारियों का कार्य महज सामान्य लिपिकीय दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह न्यायिक कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध विशिष्ट एवं विधिक प्रकृति का दायित्व है। इसलिए कार्य की प्रकृति, उत्तरदायित्व और कार्यभार के अनुरूप उनकी सेवा–शर्तों एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाना समय की

आवश्यकता है।

संघ के अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा आंदोलन का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संघर्ष के तृतीय चरण का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि शासन द्वारा न्यायालय कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो प्रदेश संघ के आह्वान पर 25 अक्टूबर को प्रदेशभर के न्यायालय कर्मचारी लखनऊ में एकत्र होकर सत्याग्रह करने के लिए बाध्य होंगे। संघ के सचिव संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लिपिकीय संवर्ग का प्रारंभिक वेतनमान 2800 ग्रेड पे (लेवल–5) निर्धारित किए जाने तथा भर्ती की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत एफटीसी में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को तत्काल 10 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने एवं उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत शिथिलीकरण, 4600 ग्रेड पे वाले पदों को राजपत्रित दर्जा प्रदान किए जाने, न्यायालयों में बयान लेखक के पद सृजित किए जाने, मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किए जाने तथा जनपद न्यायालयों में विलुप्त किए गए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को पुनः सृजित किए जाने की मांग भी शामिल है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी और संयुक्त सचिव रोहित कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के जनपद न्यायालय लंबे समय से कर्मचारियों की कमी और बढ़ते कार्यभार का सामना कर रहे हैं। अतः कार्य की प्रकृति एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नए पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है। जब तक नए पदों का सृजन नहीं हो जाता, तब तक अतिरिक्त कार्य का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों को उचित अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। संघ के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी उमेश चंद्र जायसवाल एवं क्रीड़ा सचिव जैनेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय कर्मचारियों का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, सुदृढ़ और कार्यकुशल बनाने के लिए उनकी जायज सेवा–संबंधी अपेक्षाओं के समाधान का प्रयास है।

तिरंगा यात्रा में अमित कुमार श्रीवास्तव, नियाज अहमद, अवध बिहारी श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव, सुमित झा, जैनेन्द्र कुमार यादव, मनोज कुमार, राम चंद्र यादव, वैशाली गुप्ता, आराधना, प्रिन्सी, अंजू सागर, अजय प्रकाश श्रीवास्तव, शिवम तिवारी, संदीप शुक्ला, अश्वनी पाण्डेय, मनोज कुमार श्रीवास्तव, शत्रुघ्न पांडे, अंकित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार, रामगोविंद, राधेश्याम सिंह, विनय प्रसाद तिवारी, मेराजुद्दीन, आशीष विश्वकर्मा, सतीश कुशवाहा, संजय सोनकर, प्रभाकर पाठक, विजय, बृजेश, निखिल, कुलदीप द्विवेदी, सालिक राम यादव, नीरज कुशवाहा, खुशबू गौतम, दीपक कुमार श्रीवास्तव सहित सैकड़ों न्यायालय कर्मचारी शामिल रहे।

राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा महानगर के गांवों में घुसा पानी

संवाददाता–गोरखपुर। नेपाल से आ रहे पानी के कारण राप्ती नदी के जलस्तर में शुक्रवार को भी बढ़ जारी रही। शुक्रवार सुबह आठ बजे राप्ती नदी बर्डघाट में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। राहत की बात यह है कि राप्ती नदी के बढ़त की गति थमी है।

16 घंटे में नदी सिर्फ चार सेंटीमीटर ही बढ़ी है। सरयू नदी के जलस्तर में भी कमी आ रही है लेकिन बरहज में नदी खतरे के निशान से अब भी 1.55 मीटर ऊपर बह रही है इसलिए राप्ती नदी का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। जब सरयू नदी में जलस्तर कम होता है तो राप्ती नदी भी घटना शुरू करती है। बड़हलगंज के पटनाघाट में सरयू से मिलने वाली राप्ती का पानी बरहज होते हुए बलिया के तुर्तीपार में गंगा नदी में मिलती है।

गोर्रा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शुक्रवार सुबह आठ बजे नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। रोहिन नदी अब खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर चली गई है। नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राप्ती नदी की तेजी में कमी आएगी। राप्ती के जलस्तर में बढ़त को देखते हुए महानगर के आसपास के गांवों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। नाव लगा दी गई है। बहरामपुर दक्षिणी, बहरामपुर उत्तरी, शेरगढ़ के साथ ही खिरवनिया गांव और आसपास के गांवों के ग्रामीणों को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए स्टीमर पहले ही लगा दिया गया है।

बसपा ने खोला पहला पत्ता, दयाराम राजभर जलालपुर से प्रत्याशी

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जलालपुर में चुनावी तैयारियों को धार देते हुए अपना पहला पत्ता खोल दिया है। शुक्रवार को आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी सुप्रीमों पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर मंडल जोन प्रभारी डॉ. दयाराम राजभर को जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रभारीध्प्रत्याशी घोषित किया और सम्मेलन में संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया गया। पूर्व ब्लाक प्रमुख एवं अयोध्या मंडल प्रभारी राम नयन निर्दोष के संयोजन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व नेता विधान परिषद दिनेश चंद्रा ने की, जबकि संचालन मुख्य मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल ने किया। प्रत्याशी की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल ने पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेताओं पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने सामान्य कार्यकर्ताओं को राजनीतिक जिम्मेदारियां और अवसर

दिए, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद कुछ नेता ही बसपा पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने बसपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के पीडीए राजनीतिक नारे पर भी तंज कसा और सपा के हाल में घोषित प्रत्याशियों का हवाला देते हुए उस पर सवाल उठाए। उनके संबोधन का बड़ा हिस्सा बसपा के पुराने शासनकाल की उपलब्धियों और संगठन को आगामी चुनाव के लिए सक्रिय करने पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि अंबेडकरनगर बसपा और मायावती की राजनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है यह उन की कर्मभूमि भी है। सम्मेलन में जुटी भीड़ का हवाला देते हुए उन्होंने जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा। सम्मेलन को पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा, जिलाध्यक्ष सुनील सावंत, केडी गौतम, राम नयन निर्दोष, मनोज वर्मा, रवि प्रकाश मौर्य, मोहम्मद असद, समीर चौधरी और अरविंद गौतम समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। पूर्व में अतिथियों का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया। अंत में मुख्य आयोजक डॉ. दयाराम राजबर ने सभी के प्रति आभार जताया।

गांधी जयंती पर जगह–जगह हुए कार्यक्रम

संवाददाता–संतकबीरनगर। एसडी एकेडमी धनघटा में शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धा व उत्साह से मनाई गई। इसका मकसद छात्रों को गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सादगी जैसे मूल्यों से प्रेरित करना था। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण और विशेष प्रार्थना सभा से हुई। इसमें छात्रों और शिक्षकों ने गांधीजी व शास्त्री जी को पुष्पांजलि दी।

छात्रों ने गांधीजी व शास्त्री जी के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर भाषण व लघु नाटिकाएं प्रस्तुत कीं। स्कूल में स्वच्छता अभियान भी चला, स्वच्छ भारत अभियान का महत्व समझाया गया। गांधीजी के विचारों और उनकी प्रासंगिकता पर चित्रकला व निबंध प्रतियोगिताएं भी हुईं। कार्यक्रम का समापन गांधीजी के प्रिय भजन "रघुपति राघव राजा राम" के सामूहिक गायन से हुआ, जिससे देशभक्ति का माहौल बन गया।

इस मौके पर डायरेक्टर सिंटू पाठक, पियूष, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रिया राय, कॉर्डिनेटर अरविंद पाण्डेय, अमृता राय, अंजली, रागनी राय, चंचल, सपना, आरती और प्रियंका मौजूद थीं

धनघटा के रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज ठकुराडाड़ी में शुक्रवार को गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान के तहत एक रैली निकाली। कैडेट्स ने श्रमदान करते हुए विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की। उन्होंने ष्एक पेड़ मां के नामष अभियान के तहत कई तरह के पौधे भी लगाए।

इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने ष्स्लोगन राइटिंगष प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम में कुल 16 जेडी और 8 जेडब्ल्यू कैडेट्स मौजूद रहे।

दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की हुई पैरेंट काउंसलिंग

–दिव्यांग बच्चों के लिए सहज विद्यालयी वातावरण जरूरी –मनोज मिश्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग के समेकित शिक्षा अनुभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के परामर्श के लिए शुक्रवार को विकास खंड हर्रैया के प्राथमिक विद्यालय पड़री मिश्र में पैरेंट काउंसलिंग का आयोजन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद और जिला समन्वयक सुनील त्रिपाठी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एआरपी मनोज मिश्र ने की।

स्पेशल एजुकेटर उर्मिला द्विवेदी और देवेंद्र ओझा ने अभिभावकों को दिव्यांग बच्चों के दैनिक क्रियाकलाप, शिक्षा, विद्यालय में नामांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी), ब्रेल किट, सहायक उपकरणों के वितरण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। एआरपी मनोज मिश्र ने समावेशी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों को विद्यालयी परिवेश में सहज और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों के विद्यालयी परिवेश में अनुकूलन, शैक्षिक सहभागिता तथा उनके लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के संबंध में अभिभावकों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने बच्चों की शिक्षा और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को भी साझा किया। कार्यक्रम में संजीव सिंह, मो. शमीम अंसारी, प्रवेश कुमार, सरिता मिश्र, मनोज वर्मा, अमरचंद वर्मा, साहबान अली सहित बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे।

ड्यूटी छोड़कर सिपाही सपा से विधायक बनने निकला, बोला– अखिलेश यादव को सीएम बनाइए

संवाददाता–संतकबीरनगर। डायल–112 में तैनात सिपाही श्याम सुंदर चौहान ड्यूटी छोड़कर समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वह एक साल तक सेटिंग बनाकर ड्यूटी से गायब रहा। उसकी हाजिरी बराबर लगती रही। 3 महीने पहले अफसरों को भनक लगी तो उसे सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भी सिपाही पुलिस लाइन में हाजिर नहीं हुआ। कभी वह सपा के बड़े नेताओं के स्वागत का पोस्टर जारी करता है। मंच से अखिलेश यादव को सीएम बनाने की अपील करता है। लाल टोपी लगाए फोटो के साथ लिखता है– लाल टोपी पहनकर चलो, समाजवाद संग आगे बढ़ो।

करीब एक महीने पहले संतकबीर नगर के धनघटा में सपा की समीक्षा बैठक थी। तब सिपाही श्याम सुंदर ने कहा था– मैं अनुसूचित जाति, दलित जाति से हूं। अभी भाजपा के जितने दलित विधायक और सांसद हैं, वे दलितों का वोट लेकर आरक्षण खत्म करने वाले का साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अंतिम चुनाव होगा। अगर हम और आप सभी नहीं चेते, तो चुनाव और संविधान खत्म हो जाएगा। साथ आइए और अखिलेश यादव को सीएम बनाइए।

सिपाही ने कहा– मैं शुरू से ही सपा की नीतियों से प्रेरित रहा हूं। पुलिस विभाग में रहकर पब्लिक को न्याय नहीं दिला पा रहा था। इसलिए विधायक बनने का विचार आया। तीन साल से क्षेत्र में सक्रिय हूं। लोगों की मदद कर रहा हूं। सिपाही श्याम सुंदर चौहान मूल रूप से संतकबीर नगर के महुली थाना के नैना झाला गांव के रहने वाले हैं। वह यूपी पुलिस के 1994 बैच के सिपाही हैं। उनके तीन बच्चे (एक बेटा और दो बेटियां) हैं। अब तक 11 जिलों में तैनात रह चुके हैं। साल 2023 में कुशीनगर से ट्रांसफर होकर गोरखपुर में डायल 112 में तैनाती मिली।

बताया जा रहा है कि गोरखपुर में तैनाती के दौरान ही सिपाही श्याम सुंदर ने संतकबीर नगर की धनघटा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर सबसे पुरानी पोस्ट साल 2023 की है। इसमें सिपाही ने धनघटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी थीं। इसके बाद से वह लगातार सोशल मीडिया पर क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों और अपनी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित पोस्ट करते रहे हैं। श्याम सुंदर लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहकर क्षेत्र में प्रचार कर रहा है। वह धनघटा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहा। सोशल मीडिया पर उसके कई फोटो और वीडियो सपा का प्रचार करते हुए पोस्ट हैं। हालांकि, उसके अनुपस्थित रहने के दौरान ड्यूटी पर उसकी हाजिरी कैसे दर्ज हुई, इस बारे में विभागीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। श्याम सुंदर ने सोशल मीडिया और प्रचार में समाजवादी पार्टी के बैनर का इस्तेमाल किया है। पोस्टर में उसकी तस्वीर और नाम के आगे 'सिपाही' लिखा है। एक पोस्टर में वह लाल टोपी पहने नजर आ रहा है। उसके साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसी को देखते हुए धनघटा सीट पर भी राजनीतिक दलों और संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ी है। श्याम सुंदर भी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसने पार्टी नेतृत्व से टिकट मिलने पर चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है।

महीनेभर पहले धनघटा विधानसभा क्षेत्र के लोहरेया में सपा के बूथ अध्यक्ष, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी की समीक्षा बैठक हुई थी। इसे श्याम सुंदर ने संबोधित किया था। कहा– मैं श्याम सुंदर चौहान सिपाही आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्षों का यह सम्मेलन चल रहा है। पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस पर गहन विचार चल रहा है। जो बूथ जीतेगा, वही सिकंदर होगा। जो अपना बूथ जिता लेगा, वही सरकार बनाएगा।

सिपाही नौकरी खुद नहीं छोड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो इसके पीछे वजह ये है कि वह चाहता है कि पुलिस विभाग उसे बर्खास्त करे। ताकि चुनाव में हारने या कोई ऊंच–नीच होने पर वह कोर्ट की मदद से एक बार फिर नौकरी पा सके।

गोवंशियों के अवशेष मिलने पर भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाददाता–गोरखपुर। धन निरंकार आश्रम के पास शुक्रवार की सुबह सड़क किनारे गोवंशियों के अवशेष मिलने धौसहर गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। ट्रैक्टर–ट्राली और पेड़ की डाल रखकर गोला–कौड़ीराम मार्ग जाम कर दिया गया। करीब एक घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच मान–मनौव्वल चलता रहा। पुलिस की ओर से 36 घंटे के भीतर आरोपितों की गिरफ्तारी का भरोसा दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।

धौसहर उर्फ बेलवाबारी गांव में समय माता मंदिर मार्ग स्थित धन निरंकार आश्रम के पास का है। सुबह छह बजे गोवंशियों के अवशेष मिलने की सूचना आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अवशेषों को एकत्र कराया और जेसीबी की मदद से जमीन में दफना दिया। इसके बाद भी ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि भोर में पशुओं को काटने के बाद उनके मांस वाले हिस्से वहां से ले जाए गए और अवशेष आश्रम के पास छोड़ दिए गए। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि सुबह टहलने वालों के पहुंचने पर मौके पर मौजूद लोग भाग निकले। हालांकि, इन दावों की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। पुलिस घटना की वास्तविक स्थिति और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच कर रही है। जाम की सूचना पर गोला पुलिस के साथ बांसगांव और गगहा थाने से भी पुलिस बल बुलाया गया। गोला–कौड़ीराम मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपितों की गिरफ्तारी का स्पष्ट भरोसा मिलने तक जाम हटाने को तैयार नहीं हुए।

ग्रामीणों का कहना था कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने क्षेत्र में पशु तस्करी से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच की मांग की। करीब एक घंटे तक चली बातचीत के बाद कोतवाल सीपी पांडेय ने 36 घंटे में आरोपितों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क से ट्रैक्टर–ट्राली और पेड़ की डाल हटाई और यातायात बहाल हुआ।

भाजपा नेता रतनप्रकाश दुबे, अवनीश कुमार, नवल किशोर दुबे, देवेश पांडेय, केशभान यादव और अमित कुमार समेत अन्य लोगों ने संयुक्त हस्ताक्षर वाली तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com